

# गरीब की माफी हो सकती है पर गरीब के बीमार होने की नहीं बीमार होना मना है... खट्टर सरकार के स्मार्ट बीके अस्पताल में

## ग्राउंड जीरो से विवेक की विशेष रिपोर्ट

मोदी सरकार की स्वास्थ्य सेक्टर की बहुप्रचारित 'आयुष्मान' स्कीम तो जब आएगी तब आएगी। फिलहाल, भारत में गरीब होना अभिशाप है और शायद सबसे बड़ा पाप है गरीब हो कर बीमार पड़ना। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के स्मार्ट बीके अस्पताल की कुव्ववस्था से उपजी मरीजों और उनके अभिभावकों की दयनीय दशा देख कर ऐसा आभास होना लाजमी है। यहाँ बजट और प्रचार की कमी नहीं लेकिन इलाज के नाम पर हैं बस धक्के और धक्के।

फरीदाबाद शहर वर्ष 2016 से ही भाजपा सरकार की फ्लैगशिप स्कीम के तहत स्मार्ट सिटी के लिए चयनित है। बीके अस्पताल को शहर का स्मार्ट अस्पताल घोषित किया गया है। अस्पताल को स्मार्ट बनाने के लिए झूठे वादों के अलावा भी कुछ किया गया है, ये कह पाना मुश्किल है।

मुकेशी देवी जिला एटा, उत्तर प्रदेश से साल भर पहले सपरिवार पलायन कर फरीदाबाद बाईपास के किनारे एक कमरा किराये पर लेकर रहती हैं और सेक्टर 9 की कोठियों में साफ सफाई का काम करती हैं। कुछ दिनों से दाहिने हाथ में दर्द की शिकायत लिए यहाँ वहाँ कई प्राइवेट डाक्टरों के पास इलाज कराने गईं जिन्होंने गरीब से 2000 रुपये सिर्फ पट्टी करने में लूट लिए। उन्हें बीके अस्पताल की जानकारी न होने के कारण यह रिपोर्टर उन्हें वहाँ ले गया।

इस स्मार्ट अस्पताल में सिर्फ पंजीकरण की लाइन इतनी लम्बी है कि कमजोर दिल वाले शायद ही झेल सकें। सभी के हाथ में आधार कार्ड चमक रहे थे। जिज्ञासावश पूछने पर पता चला कि पंजीकरण के लिए आधारकार्ड आवश्यक है। लाइन में लगे कई लोगों ने बताया कि आधार कार्ड न होने के कारण पहले भी घंटों खड़े रहने के बावजूद उन्हें वापस जाना पड़ा था।

पूरे एक घंटे लाइन में बिताने के बाद मुकेशी का नंबर आया तो आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की मांग की गई। मुकेशी देवी ने बताया कि आधार कार्ड और मोबाइल उनके पास नहीं है, इसपर पंजीकरण करने वाली महिला ने उन्हें डांटना प्रारंभ कर दिया। पूछने पर कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आधार को 31 मार्च 2019 तक अनिवार्य नहीं किया जा सकता, उनका कहना था कि प्रशासन को सरकार का और हमें अस्पताल प्रशासन का आदेश है, सरकार कुछ सोच समझ कर ही ऐसा कर रही होगी।

हमने बिना आधार पंजीकरण न करने की प्रक्रिया को लिखित में देने की बात कही तो पंजीकरण कार्ड इस घुड़की के साथ बन गया कि अगली बार कार्ड लेकर ही आना। विडम्बना है कि सरकार के दबाव में उच्चतम न्यायालय के आदेशों की धज्जियाँ लगभग सभी संस्थान बेरोकटोक उड़ा रहे हैं।

मुकेशी देवी को डाक्टर रवि गौड़ से इलाज कराने का नंबर मिला। कमरा नंबर 19 के बाहर मरीजों की भीड़ मधुमक्खी के छत्ते सी भनभना रही थी। अच्छे अच्छों का हौसला तोड़ सकने वाली इस भीड़ में घुसने की हिम्मत तभी हो सकती है जब आप गरीबी के बोझ तले मर रहे हों। 'स्मार्टनेस' का आलम देखिये कि हड्डी की समस्या से जूझते मरीज घंटों खड़े रहेंगे, जबकि किसी की टांग टूटी है किसी का हाथ तो कोई बुजुर्ग है। मुकेशी भी एक बार फिर इस नई लाइन में लग गईं।

लाइन सिर्फ उनके लिए थी जो इस भरम में थे कि लाइन में लग कर डाक्टर तक पहुंचा जा सकेगा। रूम नंबर 19 का अटेंडेंट अपनी जान पहचान के लोगों को सीधे अन्दर बुला लेता और बाकी लोग 'मैं आगे थी और मैं आगे थी' करते राह जाते। नतीजा ये कि मुकेशी अपनी जगह पर 30 मिनट तक हिली भी नहीं।

भीड़ और उमस, उसपर कुर्सी नहीं कोई पंखा भी नहीं, गर्भवती महिलायें खड़ी खड़ी बेसुध हो रही हैं, लोगों के सब्र का बाँध टूट ही गया और एक 45 वर्षीय महिला ने 10 वर्षीय बुजुर्ग को उसकी गर्भवती बहू को कुर्सी न देने के लिए मारना शुरू कर दिया। डाक्टर



मुकेशी का इलाज भी क्या खूब इलाज था। वो भी पूरे दिन का रोजगार गंवाने के बाद। न कोई हेल्प डेस्क न कोई सिस्टम जो इन असहाय लोगों का मार्गदर्शन कर सके। प्रशासन इतना लापरवाह या असंवेदनशील कैसे हो सकता है।

एक सीनियर स्टाफ ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि 65 डाक्टरों वाले इस अस्पताल में सिर्फ 32 डाक्टर हैं, इसमें से दो को ड्यूटेशन पर कहीं और भेज दिया है, दो अन्य डाक्टर कोर्ट कचहरी के काम में फंसे रहते हैं और बचे हुए 28 डाक्टरों को ही सारा अस्पताल संभालना होता है।

ये हाल तो तब है जब डब्ल्यूएचओ से दो अधिकारी अस्पताल पीएमओ के साथ आज ही के दिन अस्पताल का सर्वेक्षण कर रहे हैं। भाई साहब हम खुद बड़े शर्मिन्दा होते हैं जब मरीज हमें गालियाँ और बहुआएँ देता हुआ जाता है, या हमारे आगे रोता हुआ आता है, चिकित्सकों और सुविधाओं के अभाव ने हमें और मरीजों को आमने सामने लड़ने को रख छोड़ा है। ये कहना था 23 वर्षीय कर्मचारी का जो 2 वर्ष से यहाँ कार्यरत है।

के कमरे के बाहर क्या हो रहा है या उसे कैसे हैंडल किया जाए इसपर कोई ध्यान नहीं। ऐसा है ये स्मार्ट अस्पताल।

67 वर्षीया धर्मपाल ने बिफरते हुए कहा कि स्मार्ट के नाम पर कंप्यूटर से पर्ची बनना ही शामिल है यहाँ बाकी सब भगवान भरोसे। लोग आपस में मार काट करते रहें इससे प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता, सैकड़ों लोगों की भीड़ में बैठने के लिए सिर्फ 6 कुर्सियाँ दे कर कौन सी स्मार्टनेस दिखाना चाहते हैं ये?

एक महिला का रोना चिल्लाना रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अपने घायल पति और एक 9 वर्षीय बच्चे को लिए वो वार्ड में छान्नाओं से आवेदन मांगने शुरू कर दिये। सरकार कहती है कि जब तक कॉलेज भवन नहीं बनता तब तक पास के सरकारी स्कूल में कक्षाएँ लगेंगी। वहाँ पढायेगा कौन? पढ़ाने के लिये सेक्टर 16 ए स्थित दो सरकारी कॉलेजों से प्रोफेसरों को बुलाया जायेगा। विदित है कि उक्त दोनों कॉलेजों में पहले से ही जरूरत का आधा स्टाफ ही है। यानी जिन कॉलेजों में पहले से स्टाफ की कमी है उन्हीं कॉलेजों का स्टाफ सरकार के इस हवा-हवाई कॉलेज में अध्यापन कार्य करेगा। लगभग यही स्थिति नचोली वाले महिला कॉलेज की है।

जब इन हवा-हवाई कॉलेजों में कोई भी लड़की दाखिला लेने नहीं पहुंची और सरकार को अपना दांव फेल होता नज़र आया तो अधिकारियों ने सेक्टर 16 ए वाले दोनों कॉलेजों के स्टाफ को हड़काया। स्टाफ सारा काम छोड़ कर घर-घर भटक कर कुछ लड़कियों को बहलाने फुसलाने में सफल हो सका और उनके दाखिले उक्त हवा-हवाई कॉलेजों में कराये।



मदद की गुहार लगा रही थी। मदद के नाम पर मरीज ही आगे बड़े और आपातकाल में जाने की सलाह देने लगे। हमने महिला से बात की और पता चला कि पति एक्सिडेंट में घायल है, गहरे जख्मों के बावजूद आपातकाल वालों ने वार्ड में भेज दिया। अब पिछले 30 मिनट से वो बस आपातकाल और वार्ड के बीच में घूम रही हैं और देख तक नहीं रहा कोई।

पट्टी बंधे हाथ में एक परचा और दूसरे हाथ में छोटा बच्चा लिए 65 वर्षीय बादामी देवी सिर्फ इतना जानने को परेशान थी कि उसके नाती की एमआरआई टेस्ट फीस कैसे माफ हो? भीड़ में खड़े एक नवयुवक ने एससी-एसटी का प्रमाणपत्र या बीपीएल कार्ड होना आवश्यक बताया पर अस्पताल स्टाफ के एक कर्मचारी ने सबसे आसान तरीके का खुलासा किया कि किसी पार्षद या एमएलए से लिखा लाओ।

सभी कमरों के बाहर करीब-करीब ऐसी ही भीड़ अपनी बारी का इंतजार कर रही थी और अटेंडेंट अपनी सामाजिकता निभाते हुए लोगों को मूर्ख बनाने की स्मार्टनेस दिखा रहे थे। लगभग 2 घंटे खड़े लाइन में खड़े होने पर मुकेशी का नंबर भी आ गया और सिर्फ एक मिनट में डाक्टर ने हड्डी की समस्या का इलाज बिना कोई एक्सरे करवाये पैरासीटामोल और मलने का मलहम दे कर कर दिया।

अंदाजा लगा सकना मुश्किल नहीं है कि खुद अस्पताल प्रशासन कितने दबाव में है। जो डाक्टर संवेदनशील हो वो भी संवेदना दिखा नहीं पाएगा, न ठीक इलाज दे सकेगा।

बस हस्ताक्षर कर सरकारी आंकड़ों में इजाफा कर सकेगा। साथ ही लम्बी लाइनों में लड़ती भी? को शांत करने के लिए न कुर्सी है न पंखा। यहाँ किसी कामचलाऊ व्यवस्था के भी दर्शन क्यों नहीं? जगह-जगह पहुँच चुका टोकन सिस्टम ही क्यों नहीं लागू किया जा सकता? कम से कम इन जानलेवा लाइनों के झगड़ों से ही छुटकारा मिले।

झूठे आंकड़े जारी कर अपनी पीठ थपथपाने वाली मोदी सरकार एक ओर आयुष्मान कार्यक्रम चला कर बीमा कंपनियों और प्राइवेट अस्पतालों की जेबें गरम करने जा रही है वही दूसरी तरफ जनता को स्मार्ट का लालीपोंप देकर बजट हजम किया जा रहा है। इन चार वर्षों में स्थिति बद से बदतर होने दी गयी है।

जहाँ ज्यादा से ज्यादा चिकित्सकों और स्टाफ नर्स की भर्ती करनी चाहिए वहाँ सरकार सिर्फ बिल्लिंग और रंगरोगन के नाम पर झाँसा दे रही है। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बनाया गया है पिछले चार वर्षों में जो कह सके कि आमजन को अब कम धक्के खाने पड़ते हैं। इन धक्कों से परेशान होकर अंत में गरीब को निजी डाक्टरों, झोलाछाप और हकीमों की शरण में लुटना पड़ता है।

स्मार्ट, डिजिटल, इत्यादि का फायदा सिर्फ इतना है कि नेता अपनी जेब भर लें और सरकार पूंजीपतियों की आय को जीडीपी में दिखा कर अर्थव्यवस्था को भरमा सके तो दूसरी तरफ आप स्मार्ट फोन में उधारी के रिचार्ज से घर बैठे जान लें कि कितना बर्बाद हो चुके हैं।

## कणक बीजी नहीं, कुड़ी जन्मी नहीं, आ जवाइया मंडे खा:

### नये महिला कॉलेज इस तर्ज पर खोल रही खट्टर सरकार

फरीदाबाद ( म.मो. ) पंजाबी की उक्त कहावत भाजपा की खट्टर सरकार पर एकदम फिट बैठती है। इसका अर्थ है, गेहूँ अभी बोई भी नहीं और बेटी अभी पैदा भी नहीं हुई और जमाई को गेहूँ के आटे की विशेष रोटियाँ खाने का न्योता दे दिया।

इसका बेहतरीन नमूना बल्लबगढ़ के महिला कॉलेज का है। कॉलेज का भवन निर्माण तो क्या अभी न तो इसका नक्शा पास हुआ है न निर्माण कार्य का टेंडर हुआ है। अभी तो केवल 'हूडा' विभाग के एक पौने छह एकड़ के भूखंड को इस काम के लिये चिन्हित किया गया है। पी डब्लूडी विभाग ने इस भूखंड के जोनिंग प्लान के लिये फ़ाइल चंडीगढ़ स्थित 'हूडा' मुख्यालय भेजी है। वहाँ से स्वीकृत होने के बाद भवन का नक्शा बनेगा, फिर टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद कोई ठेकेदार निर्माण कार्य शुरू करेगा।

परन्तु जनता को बेवकूफ बनाने के लिये सरकार ने हवा-हवाई कॉलेज के लिये

## मोदी के 18 घंटे काम करने का नतीजा देखिए

रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर

भारत महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश

स्विस बैंक में भारतीयों का काला धन 50% बढ़ा

हर घंटे दो किसान कर रहे हैं आत्महत्या

देश को बर्बाद करने के लिए ओवर टाइम कौन करता है भाई?